(3) किसी देश के लिए विशेष मौसमी कारणों की वजह से कुछेक कीटनाशी दवाइयों का स्वीकार न किया जाना,

(4) पशुओं तथा पर्यावरण में फैले जाने वाले अवशेषों संबंधी स्थानीय अध्ययन,

(5) कीटों पर कीटनाशी दवाइयों का असर होना बंद हो जाना, और

(6) पारिस्थितिक कारक।

(ग) हमारे देश में इन कीटनाशी दवाइयों के इस्तेमाल पर अब तक रोक न लगाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(1) सुरक्षित/सस्ती वैकल्पिक दवाइयों का उपलब्ध न होना अर्थात् जन-स्वास्थ्य में डी०डी०टी०।

(2) विशेष कृमियों और रोगों की स्थिति से निपटना।

(3) शीतोष्ण क्षेत्र के देशों की तुलना में भारतीय पर्यावरण में कीटनाशी दवाइयों की प्रभाविकता तेजी से समाप्त होना।

(4) अनुसंधान और विस्तार एजेंसियों द्वारा संस्तुत ध्यानपूर्वक विचारित इस्तेमाल के तरीके।

चीनी का उत्पादन

1882 **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के पिराई मौसम की तुलना में इस वर्ष चीनी का उत्पादन अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है,

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अवधि के दौरान देश में चीनी की खपत बढ़ी है,

(घ) यदि हां, तो अनुमानित खपत कितनी है, और

(ङ) देश में चीनी की वर्तमान मांग को दृष्टि में रखते हुए अगले वर्ष के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या प्रोत्साहनकारी कदम उठा रही है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० बैता): (क) और (ख) जी। हां। 22.2 1989 को स्थिति के अनुसार चालू मौसम के दौरान 55.25 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ जबकि पिछले मौसम में उसी अवधि के दौरान 49.49 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(ग) जी हां।

(घ) चालू गौसम के दौरान चीनी की खपत पिछले वर्ष 93.33 लाख मीटरी टन की हुई खपत की तुलना में अधिक होने का अनुमान है।

(ङ) मौसम की स्थितियों और अन्य संगत तथ्यों के कारण गन्ने के उत्पादन में उतार-चढ़ाव होने की वजह से आगामी मौसम 1989-90 के लिए चीनी के उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें प्रत्येक वर्ष गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करना, सांविधिक न्यूनतम मूल्य की पेशगी घोषणा करना, लेवी से मुक्त बिक्री के कोटे के अनुपात में परिवर्तन करना, नयी चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस देना, वर्तमान क्षमताओं में विस्तार करना, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं और आधुनिकीकरण तथा गन्ने के विकास के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल हैं।

Conference of Food and Civil Supplies Ministers of States and Union Territories

1883. SHRI KAPIL VERMA
SHRIMATI VEENA VERMA:
KUMARI SUSHILA TIRIA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR.

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to reply to Starred Question 58 given in the Rajya Sabha on the 24th February, 1989 and state whether any conference of Food and Civil Supplies Ministers from States and Union Territories was held recently; if so, action taken on their recommendations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D.L. BAITHA): No Conference of Food and Civil Supplies Ministers of all States and Union Territories was held recently to discuss about price situation of essential commodities.

Withdrawal of concessional rate of excise duty on diesel oil used by deep sea fishing trawlers

1884 SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Deep sea industry has expressed its concern over the sudden withdrawal of the concessional rate of excise duty of diesel oil used by deep-sea fishing trawlers;

(b) whether this decision of Government is likely to have an adverse impact on the export of marine products and is also likely to make Indian exports uncompetitive in the world markets; and

(c) if so, whether Government propose to review its decision?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER) (a) to (c) withdrawal of concessional rate of excise duty on diesel oil used by deep sea fishing vessels was announced by the Government in December, 1988 It is too early to say whether it would make Indian marine exports uncompetitive in the world market.

Recommendations of National Commission on Urbanisation

1885. SHRI KAPIL VERMA
SHRIMATI VEENA VERMA
KUMARI SUSHILA TIRIA

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the main recommedations of the National Commission on Urbanisation during the last three years and what action has been taken thereon, and

(b) what action has been taken on recommendations to improve the financial and managerial capacity of local bodies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) and (b) A copy of the main recommendations of the National Commission on Urbanisation is annexed [*see* Appendix CXLIX, Annexure No. 105]. The recommendations of the Commission have been circulated amongst the State Govts. / UT Administrations, Central Ministries / Deptts. Expert Groups and other Agencies for their comments, as also an action comtemplated by them in pursuance of Commission's recommendations Based on the comments received from various agencies, an action plan will be prepared. So far as improving the financial and managerial capacity of the Local Bodies is concerned, an infrastructure window has been set-up in HUDCO in order to extend loan assistance for viable schemes to augment municipal infrastructure. The recommendations of the Commission as regards, finance have been considered and broadly endorsed by the Central Council of Ministers for Local Government and Mayors The Question of stepping up the plan outlay would be taken up with the Planning Commission. Since the Local Bodies are entirely within the Administrative Jurisdiction of State Governments, they have been requested